भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 346

21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- बार-बार आने वाली बाढ़ और नदी अपरदन का कृषि उत्पादकता पर प्रभाव

346. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम में बार-बार आने वाली बाढ़ और नदी अपरदन का कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान नष्ट हुई कृषि योग्य भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा प्रदान किया गया है; और

(घ) कृषि आजीविका के संरक्षण हेतु क्या दीर्घकालिक न्यूनीकरण उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध निधि से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, कारित हुई/दावा की गई हानियों के मुआवजे के लिए नहीं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान असम में शुद्ध बोया गया क्षेत्र निम्न प्रकार है (हजार हेक्टेयर में):

कृषि वर्ष	शुद्ध बोया गया क्षेत्र
2020-21	2724
2021-22	2749
2022-23	2744
2023-24	2756
2024-25	2759

पिछले 5 वर्षों के दौरान असम में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ग): असम राज्य को पिछले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान एसडीआरएफ से 3793.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इनमें से 3414.40 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी किए गए। पिछले पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान एनडीआरएफ से असम को 1001.377 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(घ): जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बाढ़ प्रबंधन एवं अपरदन रोधी योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। केंद्र सरकार बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत वर्ष 2021-26 की अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण, अपरदन रोधी उपाय, जल निकासी विकास आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की "भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का आकलन" नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1986 से 2022 तक के उपग्रह इमेजरी डेटा के आधार पर, भारत में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 21.213 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) आंका गया है, और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न बाढ़ प्रबंधन उपायों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र 20.538 मिलियन हेक्टेयर है। असम राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2.477 मिलियन हेक्टेयर है।

असम सरकार ने बाढ़ के प्रति कृषि की सहनशीलता बढ़ाने के लिए कई दीर्घकालिक उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बाढ़ और जलमग्नता सहिष्णु फसल किस्मों का वितरण।
- जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाओं, समय पर जारी सलाहों और उपयुक्त फसल प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- सूखे के दौरान पानी की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और अन्य जल संरक्षण उपायों सहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन।
- रबी मौसम के दौरान उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों सहित कुशल जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- आधुनिक कृषि मशीनीकरण और उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के सहयोग से किसानों को दलहन, तिलहन और सब्जियों जैसी रबी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करके फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना ने देश के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कृषि में जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रचार किया है। एनआईसीआरए के तहत स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाता है। असम के दरांग, धेमाजी, धुबरी और नलबाड़ी जिलों में जलवायु परिवर्तन के बावजूद फसल पैदावार बढ़ाने वाली जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

******